



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, ९ जून, १९९८/१९ ज्येष्ठ, १९२०

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

विधायी एवं राजभाषा खण्ड

अधिसूचना

शिमला-२, ९ जून, १९९८

संख्या एल० एल० आर० (राजभाषा)बी०(१६)-८/९८.—“दि हिमाचल प्रदेश पैसैंजर एण्ड गुड्ज टैक्सेशन (अप्रैन्डमेंट) ऐक्ट, १९६६ (१९६६ का ७)” के राजभाषा (हिन्दी) अनुवाद को हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के तारीख २ जून, १९९८ के प्राधिकार के अधीन एतद्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

और यह हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 के अधीन उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-

सचिव (विधि),

हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) अधिनियम, 1966

(1966 का 7)

(14 अप्रैल, 1966 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमत)

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (1955 का 15) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्रहवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) अधिनियम, 1966 है। संक्षिप्त नाम।

2. हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (ख) में, “वित्तायुक्त (Financial Commissioner)” शब्द के स्थान पर “आबकारी और कराधान आयुक्त” शब्द रखे जाएंगे। धारा 2 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

धारा 3 का संशोधन।

(क) उप-धारा (1) में,—

- (i) “पर एक पाई प्रति आना” शब्दों के स्थान पर “के बारहवें भाग” शब्द रखे जाएंगे;
- (ii) “तीन पाई” शब्दों के स्थान पर “दो पैसे” शब्द रखे जाएंगे;
- (iii) “एक पैसे (तीन पाईयों) के निकट तक” शब्दों और कोष्ठक के स्थान पर “में” शब्द रखा जाएगा।

(ख) “किसी स्थान से” शब्दों के पश्चात् “या राज्य के बाहर किसी स्थान से किन्तु राज्य के बीच से राज्य के बाहर किसी स्थान को अथवा राज्य के भीतर किसी स्थान से किन्तु अन्य मध्यवर्ती राज्य क्षेत्र के बीच से” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

4. मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

धारा 4 का संशोधन।

“परन्तु सार्वजनिक वाहनों (Public Carriers) या वैयक्तिक वाहनों (Private Carriers) की दशा में, सरकार भाड़े के सम्बन्ध में देय कर के बदले में विहित रीति से एक मुश्त राशि ले सकेगी :

परन्तु यह और कि ठेका गाड़ियों (Contract Carriages) की दशा में सरकार किराए के सम्बन्ध में विहित रीति से एक मुश्त राशि ले सकेगी”।

धारा 9 का संशोधन। 5. मूल अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) में, "उसके लिए" शब्दों के पश्चात् आए शब्द "उस जिले के" शब्दों और "दिया हो" शब्दों के पश्चात् आए शब्द "जिसमें मोटर विहिकल ऐक्ट, 1939 (Motor Vehicles Act, 1939) के अधीन उसकी मोटर गाड़ी पंजीयित हो" शब्दों का लोप किया जाएगा।

धारा 13 का संशोधन। 6. मूल अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3) विहित प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि मोटरगाड़ी के स्वामी द्वारा इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का अपवंचन तो नहीं किया जा रहा है, ऐसी मोटरगाड़ी की लाग बुक का निरीक्षण कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो, तो ड्राइवर से लाग बुक का अभिग्रहण कर सकेगा और उसके लिए ड्राइवर को अस्थायी अभिस्वीकृति देगा।"

धारा 13-क का अन्तः-स्थापन। 7. मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"13-क. (1) विहित प्राधिकारी, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से आरोपित किसी मोटरगाड़ी का ड्राइवर फरार हो जाएगा या अन्यथा समन की तामील से अपने आप को बचाएगा, ऐसे ड्राइवर द्वारा धारित किसी अनुज्ञप्ति का अभिग्रहण कर सकेगा और इसे अपराध का संज्ञान करने वाले न्यायालय को अग्रेषित करेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति का अभिग्रहण करने वाला विहित प्राधिकारी, उसके लिए अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित करने वाले व्यक्ति को अस्थायी अभिस्वीकृति देगा और ऐसी अभिस्वीकृति धारक को तब तक गाड़ी चलाने के लिए प्राधिकृत करेगी जब तक कि उसे अनुज्ञप्ति वापस नहीं कर दी जाती है या न्यायालय ने अन्यथा आदेश न दिया हो।"